



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2017/फाल्गुन 2, 1938

No. 479]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2017/PHALGUNA 2, 1938

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

का.आ. 535(अ).—जबकि, भारत सरकार ने 24 अक्तूबर, 2014 को एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (इसके पश्चात् बैंक कहा जाएगा) की स्थापना के संबंध में एक अंतर-सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए;

और जबकि, भारत सरकार ने दिनांक 29 जून, 2015 को बैंक की स्थापना से संबंधित करार के अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर किए और उक्त करार को 18 दिसम्बर, 2015 को अनुसमर्थित किया;

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेदों के अध्याय IX के अनुच्छेदों 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 के तहत इस बैंक, उसके प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति का प्रावधान है;

और जबकि, केंद्रीय सरकार विचार करती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत प्रदत्त आवश्यक विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति इस बैंक, इसके प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रदान करना समीचीन होगा;

अब, अतः संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद I की धारा 1, अनुच्छेद II की धारा 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7, अनुच्छेद III की धारा 9, अनुच्छेद V की धारा 18 के खंड (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) तथा धारा 20, अनुच्छेद VI की धारा 22 के खंड (क), (ख), (ग), (ङ) और (च) के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक तथा उसके प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों पर लागू होगा।

[फा. सं. डी-II/451/16(2)/2017]

संजय वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2017

S.O. 535(E).—Whereas, the Government of India signed an inter-governmental Memorandum of Understanding for establishing the Asian Infrastructure Investment Bank (hereinafter referred to as the Bank) on 24th October, 2014;

And whereas, the Government of India signed the Articles of Agreement establishing the Bank on 29th June, 2015 and ratified the said Agreement on 18th December, 2015;

And whereas, Article 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 of Chapter IX of the Articles of the said Agreement provide for privileges and immunities of the Bank and its representatives and officials;

And whereas, the Central Government considers it expedient to extend the necessary privileges and immunities provided under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) to the Bank and its representatives and officials;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of section 1 of Article I, sections 2,3,4,5,6 and section 7 of Article II, section 9 of Article III, clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of section 18 and section 20 of Article V and clauses (a), (b), (c), (e) and (f) of section 22 of Article VI of the Schedule to the said Act shall apply, *mutatis mutandis*, to the Asian Infrastructure Investment Bank, its representatives and officials.

[F. No. D-II/451/16(2)/2017]

SANJAY VERMA, Jt. Secy.